IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

राज्य में प्राथमिक शिक्षा के महत्व को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं का विश्लेषणात्मक अध्ययन

प्रीति कुमारी
पीएच.डी. शोधार्थी
बीआरए बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर, बिहार

सार

हमारे गणतंत्र की शुरुआत के बाद से, सभी को समान अवसर प्रदान करके लोकतंत्र के सामाजिक ताने-बाने को मजबूत करने में सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा (यूईई) के महत्व को मान्यता दी गई है। राज्य को 14 साल से कम उम्र के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के लिए हर संभव प्रयास करने के लिए संविधान के राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों के अनुच्छेद 45 द्वारा आवश्यक था। इस संदर्भ में, बिहार की राज्य सरकार ने विद्यार्थियों को शामिल करने के प्रयास किए हैं। गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने के लिए समाज के विभिन्न वर्गों से।

कीवर्ड: राज्य, निदेशक सिद्धांत प्रारंभिक शिक्षा, समान अवसर, अधिकार-आधारित ढांचा, नीतियां

1. परिचय

अधिकार-आधारित ढांचे की ओर सभी को समान अवसर प्रदान करके लोकतंत्र के सामाजिक ताने-बाने को मजबूत करने के लिए सार्वभौमिक प्रारंभिक शिक्षा (यूईई) की भूमिका को हमारे गणतंत्र की स्थापना के बाद से स्वीकार किया गया है। संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में मूल अनुच्छेद 45 ने राज्य को दस साल की अवधि में चौदह वर्ष तक के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करने का आदेश दिया।

शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति, 1986 में अपनाई गई और 1992 और 2020 में अद्यतन की गई, एक भूमि थी भारतीय शिक्षा में निशान। इसने विकास के लिए दोनों को एक व्यापक ढांचा प्रदान किया सदी के अंत तक शिक्षा और शिक्षा के आयोजन, कार्यान्वयन और वित्त पोषण के लिए विशिष्ट जिम्मेदारियों को निर्दिष्ट करने वाली कार्य योजना। यह प्राथमिक शिक्षा को अयोग्य प्राथमिकता देता है। इस तथ्य को स्वीकार करते हुए कि निकट भविष्य में सभी बच्चों तक प्राथमिक शिक्षा पहुंचाना एक कठिन कार्य है, औपचारिक और गैर-औपचारिक शिक्षा दोनों क्षेत्रों में अभिनव, लचीले हस्तक्षेपों की एक व्यवस्थित सरणी की योजना बनाई जा रही है और इसे पूरे देश में लागू किया जा रहा है। इन हस्तक्षेपों का मुख्य फोकस समाज के सबसे वंचित समूहों, विशेषकर बालिकाओं पर है।

2. अनुसंधान पद्धति और डेटा स्रोत

प्रस्तुत अध्ययन बिहार में प्रारंभिक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए विभिन्न प्रायोजित कार्यक्रमों के दृष्टिकोण और प्रभावों की जांच करता है। यह अध्ययन केवल सरकारी स्कूलों पर केंद्रित है। प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता पर कार्यक्रम/योजना के प्रभाव को मापने के लिए माध्यमिक डेटा यहां नियोजित किया गया है। ये डेटा स्रोत DISE और ASER हैं। हालांकि, बुनियादी ढांचे की सुविधा की उपलब्धता को मापने के लिए 2002 से 2019 तक डीआईएसई डेटा का उपयोग किया जाता है। दूसरी ओर छात्र के सीखने के कौशल की जांच के लिए 2007 से 2018 तक एएसईआर डेटा का उपयोग किया जाता है।

3. विश्लेषण परिणाम और चर्चा

निम्नलिखित कार्यक्रमों को राज्य सरकार (बिहार सरकार), केंद्र सरकार (भारत सरकार) और यूनिसेफ द्वारा क्षेत्र के शिक्षा स्तर को ऊपर उठाने के लिए संयुक्त रूप से प्रायोजित किया गया है:

3.1. सर्व शिक्षा अभियान (केंद्र सरकार)

सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) सार्वभौमिक प्रारंभिक शिक्षा के लिए एक कार्यक्रम है। यह कार्यक्रम एक मिशन मोड में सामुदायिक स्वामित्व वाली गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के प्रावधान के माध्यम से सभी बच्चों को मानवीय क्षमताओं में सुधार करने का अवसर प्रदान करने का एक प्रयास भी है। यह पूरे देश में

गुणवत्तापूर्ण बुनियादी शिक्षा की मांग की प्रतिक्रिया है। बिहार में, इसे बिहार शिक्षा परियोजना के रूप में लागू किया गया था।

3.2. बिहार शिक्षा परियोजना (केंद्र सरकार, राज्य सरकार और यूनिसेफ / विश्व बैंक)

बिहार शिक्षा परियोजना योजना और कार्यान्वयन की बुनियादी इकाई के रूप में जिले का उपयोग करते हुए सभी के लिए शिक्षा (ईएफए) के लिए समग्र दृष्टिकोण को शामिल करने के लिए भारत में पहले बड़े प्रयास का प्रतिनिधित्व करती है। परियोजना ने एक सूक्ष्म दृष्टिकोण (ग्राम स्तर) के साथ-साथ एक मैक्रो दृष्टिकोण (राज्य स्तर) की कल्पना की थी, जो स्वायत्त निकायों की संरचना द्वारा मजबूत किया गया था और बहुपक्षीय (यूनिसेफ, भारत सरकार और बिहार सरकार) वित्त पोषण में लाया गया था। यह परियोजना शुरू में तीन जिलों - रांची, रोहतास और पश्चिम चंपारण में 1991-92 में शुरू की गई थी और बाद में चार अन्य जिलों में इसका विस्तार किया गया।

बीईपी ने प्राथमिक शिक्षा में योजना और कार्यान्वयन की एक इकाई के रूप में जिले की शुरुआत की। शैक्षिक पुनर्निर्माण प्रमुख लक्ष्य था और कार्यक्रम के घोषित उद्देश्यों को संक्षेप में निम्नानुसार किया जा सकता है:

(i) औपचारिक और गैर-औपचारिक शिक्षा के साथ-साथ एमएलएल की सार्वभौमिक उपलब्धि के माध्यम से नामांकन और प्रतिधारण सहित 14 वर्ष तक के सभी बच्चों तक पहुंच सहित प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण

(ii) लड़कियों और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के बच्चों को समान अवसर प्रदान करने के लिए शैक्षिक प्रणाली में संशोधन करना; तथा

(iii) गरीब लोगों के काम करने और रहने की स्थिति से शिक्षा का संबंध

कार्यान्वयन घटक

- औपचारिक प्राथमिक शिक्षा
- पूर्व-प्राथमिक शिक्षा और प्रारंभिक बचपन की देखभाल
- महिला समाख्या
- प्रशिक्षण
- संस्कृति, सतत शिक्षा और सामान्य पर्यावरण भवन
- अनौपचारिक प्राथमिक शिक्षा

- स्कूल प्रबंधन, शिक्षण-अधिगम, निर्माण, गुणवत्ता सुधार, प्रोत्साहन आदि।
- एमएलएल कार्यक्रम

बीईपी मुजफ्फरपुर कुल साक्षरता के लिए 6 स्लम क्षेत्रों को अपनाकर गरीबों के लिए शहरी बुनियादी सेवाओं का बड़े पैमाने पर समर्थन कर रहा है। सेवाकालीन शिक्षक प्रशिक्षण, प्रखंड स्तरीय निरीक्षण अधिकारियों का प्रशिक्षण और प्रधानाध्यापकों का प्रशिक्षण डाइट के प्रशिक्षण एजेंडे में पहले आइटम थे, जिसके लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा अभी भी विकास की प्रक्रिया में है।

3.3. जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (केंद्र सरकार)

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम का लक्ष्य शैक्षिक पुनर्निर्माण के माध्यम से राज्य में एक प्रेरक शक्ति लाना है। शैक्षिक स्थिति में बदलाव से सभी क्षेत्रों में सुधार आएगा और निराशा, निंदक और हिंसा का माहौल पर्यावरण, सामाजिक, सांस्कृतिक और लैंगिक मुद्दों से निपटने के लिए दृढ़ संकल्प का मार्ग प्रशस्त करेगा।

शिक्षा को सामाजिक परिवर्तन के एक साधन के रूप में देखते हुए, कार्यक्रम के दृष्टिकोण और रणनीति में अनिवार्य रूप से निम्नलिखित की परिकल्पना की गई है:

- शिक्षा की सामग्री और प्रक्रिया में सुधार
- शिक्षकों और वयस्क शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा कार्यकर्ता की सतत शिक्षा पर जोर देने के साथ प्रशिक्षण की एक विस्तृत प्रणाली बनाना
- राजनीतिक दलों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, नियोक्ताओं, ट्रेड यूनियनों और स्वैच्छिक एजेंसियों के साथ गठजोड़ करना
- शिक्षक को प्रथम स्थान पर रखना -- सभी स्तरों पर शैक्षिक परिवर्तन प्रक्रिया में मुख्य भूमिका के रूप में केंद्रीय भूमिका में
- परियोजना की गतिविधियों के मूल के रूप में महिला सशक्तिकरण
- सभी वंचित व्यक्तियों को एक प्रासंगिक, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का समान अवसर मिलना चाहिए
- सभी स्तरों पर प्रतिबद्ध लोगों के कैडर तैयार करना और उनका विस्तार करना ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि गतिविधियों का समर्थन करने के लिए एक 'महत्वपूर्ण' जन होगा।

- परियोजना की आधारशिला के रूप में भागीदारी योजना और कार्यान्वयन

3.4. समग्र शिक्षा (राज्य सरकार)

यह एक क्षेत्र-व्यापी विकास कार्यक्रम है जो सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए), राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए) और शिक्षक शिक्षा (टीई) की तत्कालीन मौजूदा केंद्र प्रायोजित योजनाओं को शामिल करता है ताकि सभी स्तरों पर कार्यान्वयन तंत्र और लेनदेन लागत में सामंजस्य स्थापित करने में मदद मिल सके। एकीकृत योजना में पूर्व-विद्यालय, प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक से वरिष्ठ माध्यमिक स्तर तक एक निरंतरता के रूप में 'विद्यालय' की परिकल्पना की गई है। योजना का दृष्टिकोण शिक्षा के लिए सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) के अनुसार पूर्व-विद्यालय से वरिष्ठ माध्यमिक स्तर तक समावेशी और समान गुणवत्ता वाली शिक्षा सुनिश्चित करना है। कार्यक्रम के प्राथमिक उद्देश्यों में शामिल हैं :

- गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का प्रावधान और छात्रों के सीखने के परिणामों में वृद्धि
- स्कूली शिक्षा में सामाजिक और लैंगिक अंतर को पाटना
- स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों पर समानता और समावेश सुनिश्चित करना
- स्कूली शिक्षा के प्रावधानों में न्यूनतम मानकों को सुनिश्चित करना
- व्यावसायीकरण को बढ़ावा देना ; बच्चों के मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम 2009 का कार्यान्वयन
- शिक्षक प्रशिक्षण के लिए नोडल एजेंसियों के रूप में एससीईआरटी और डाइट का सुदृढ़ीकरण और उन्नयन

4. निष्कर्ष

बिहार ने पिछले 50 सालों में शिक्षा के क्षेत्र में काफी तरक्की की है. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 और कार्य योजना 1992 ने भी सार्वभौमिक प्रारंभिक शिक्षा के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता दी। पिछले चार दशकों के दौरान प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण के लिए उपरोक्त चर्चा कार्यक्रमों/योजनाओं को शुरू किया गया था। इनमें से कुछ प्रयास प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में हैं और कुछ उच्च प्राथमिक क्षेत्र को भी कवर करते हैं। केंद्र सरकार की मदद से राज्य सरकार द्वारा शुरू किए गए इन हस्तक्षेपों के कारण, प्राथमिक शिक्षा क्षेत्र में पहुंच प्रदान करने, प्रतिधारण में सुधार और गुणवत्ता में सुधार करने में काफी प्रगति हुई है। हालांकि, विशेष फोकस समूहों और उच्च प्राथमिक क्षेत्र के लिए बहुत कुछ करने की जरूरत है। गुणवत्ता सुधार अभी भी एक प्रमुख चिंता का विषय बना हुआ है,

खासकर उच्च प्राथमिक क्षेत्र के लिए। इस प्रकार, प्रारंभिक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए बिहार को एक लंबा रास्ता तय करना है। अब समय आ गया है कि बिहार को छात्रों की संख्या के बजाय प्रारंभिक शिक्षा की गुणवत्ता पर ध्यान देना चाहिए।

संदर्भ

1. अखिल भारतीय शैक्षिक सर्वेक्षण रिपोर्ट, एनईसीआरटी, नई दिल्ली। (संक्षिप्त रिपोर्ट (8वीं AISES))
2. अखिल भारतीय शैक्षिक सर्वेक्षण रिपोर्ट, एनईसीआरटी, नई दिल्ली। (अनंतिम सांख्यिकी (8वीं AISES)
3. वार्षिक रिपोर्ट 2019-20 – NCERT https://www.education.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/document-reports/Annual-Report-2019-20.pdf
4. वार्षिक रिपोर्ट 2018-2019 (एलएस) – NIEPA https://www.education.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/document-reports/annual_rpt_ls.pdf
5. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 https://www.education.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/NEP_Final_English_0.pdf
6. राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन विश्वविद्यालय (विश्लेषणात्मक रिपोर्ट, फ्लैश सांख्यिकी और राज्य रिपोर्ट कार्ड), नई दिल्ली।
7. एकीकृत जिला शिक्षा सूचना प्रणाली (जिला रिपोर्ट कार्ड), एनयूईपीए, नई दिल्ली।
8. सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) के तहत बिहार शिक्षा परियोजना परिषद, पटना द्वारा सर्वेक्षण।
9. *राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, बिहार सरकार*
10. *राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, बिहार सरकार : वार्षिक रिपोर्ट (2019-20)*
11. *बिहार शिक्षा परियोजना परिषद : जिलेवार सांख्यिकीय रिपोर्ट (2019-20)*
12. *अभिलेखागार : भारत का राजपत्र*
13. *अभिलेखागार : बिहार सरकार, मानव संसाधन विकास विभाग*